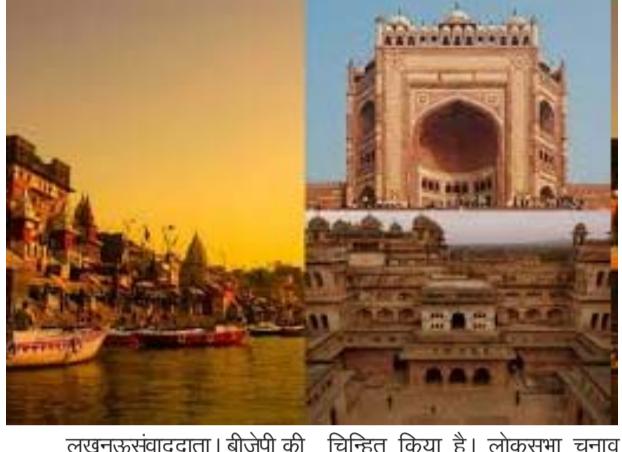


बीजेपी ने तलाश ली यूपी में किला ढहने की वजह

**मनवट प्रशासन से निराश कायकताओं में नहीं था उत्साह
घट गया आठ फीसदी गोट, सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी अगली रणनीति**



लेखन उत्तरायणीयता का जगता परा पारिषियामैट इलेक्शन में खराब प्रकारफैसल की वजह पार्टी ने पता कर ली है। भर्ती परीक्षाओं का लीक होना, राज्य में अधिकारियों को मिली हुई खुली छूट और विपक्ष द्वारा संविधान और रिजर्वेशन के मुद्दे उठाने से ओबीसी व दलित मतदाताओं का मत विभाजन, ये वो वजह हैं, जिन्हें बीजेपी ने यूपी में अपनी खराब प्रदर्शन के रूप में बताया है। यूपी का बोट शेयर 41.37 फीसदी पर पहुंच गया जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में यह 49.98फीसदी था बीजेपी ने 19 जून से 25 जून के बीच यूपी की 78 लोकसभा सीटों पर अपने प्रदर्शन की समीक्षा की। इन सीटों में पीएम नरेंद्र मोदी की वाराणसी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की लखनऊ

मैनपुरी में प्रेक्षागृह, हाल, सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय निर्माण की धीमी प्रगति पर पर्यटन मंत्री खाफा

लखनऊसंवाददाता। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में प्रक्षेपगृह एवं बहुउद्दीशीय हाल तथा सांस्कृतिक केन्द्र एवं संग्रहालय निर्माण की धीमी प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी निर्माणकार्य मार्च 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिये हैं। राज्य संग्रहालय निदेशालय तथा कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य पर फैसी नजर रखने तथा उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए भी निर्देशित किया है। नवनिर्मित प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भवन में गैस सप्रेशन सिस्टम आदि की स्थापना का कार्य इस महीने की 15 तारीख तक पूर्ण करने के लिए कहा है। पर्यटन मंत्री ने बताया कि संस्कृति निदेशालय के अधीन विभिन्न जनपदों में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। सभी निर्माणकार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि समीक्षा बैठक करके निर्धारित कर दी गयी है। कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि तय समय सीमा में सभी कार्य पूरा करें ताकि दमको आम जनता को समर्पित किया जा सके। कार्यदायी

से बीजेपी वर्कर्स कार्यकर्ताओं में निराशा ने पार्टी को चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जिम्मेदारी संगठन पर है वॉयेंकि चुनाव दल लड़ता है सरकार नहींलेकिन वोटर सरकार के प्रदर्शन के आधार पर वोट करता है राजनीतिक दल के आधार पर नहीं। कार्यकर्ता हतोत्साहित थे। लंबे समय से लोकल पुलिस स्टेशनों और तहसील कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा उनका अपमान किया जा रहा था। इसी वजह से मतदान केंद्रों में बीजेपी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं ने उत्साह नहीं दिखाया। राज्य सरकार के 'बीआईपी कल्वर' पर नकेल के फैसले ने पुलिस कर्मियों को बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने की अनुमति दे दी। वाहनों से पार्टी के झंडे उतारे गए, उनके वाहनों की जांच की गई और ट्रैफिक रूल्स के कथित उल्लंघन के लिए चालान काटे गए बीजेपी की रिव्यू मीटिंग्स में यह भी सामने आया है कि भर्ती परीक्षाओं के लीक होने से न सिर्फ युवा नाराज थे बल्कि उनके परिवार वालों के गुरुस्से का सामना बीजेपी को करना पड़ा। योगी सरकार ने पिछले महीने ही पेपर लीक से संबंधित नया कानून बनाया है। दोषी पाए जाने पर दो साल से आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये फाईन हो सकता है। अगर ये कदम पहले उठा लिया गया होता तो शायद बीजेपी को युवाओं के वोट का नुकसान न होता। कन्नौज में अखिलेश यादव से हारने वाले सुब्रत पाठक तो खुलकर पेपर लीक को पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह बता चुके हैं। एक्स पर उन्होंने पोस्ट कर कहा कि यूपी में बीजेपी की हार के कई कारण हैं लेकिन पेपर लीक बड़ी वजह है। अट्टाचार ने शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जाति और समुदायों वोटों को लेकर कैलकुलेशन गलत साबित हुई। इसमें खासतौर पर दलित और ओबीसी में तो यही हुआ। विषय के कैंपन की वजह से आरक्षण और संविधान पर विषय के अभियान के कारण दलितों और ओबीसी के करीब 8 फीसदी वोट कट गए। बीएसपी के वोट बेस में अच्छी संख्या में जाटव मतदाता सपा और कांग्रेस में शिफ्ट हो गए। आरक्षण और संविधान पर कैंपन की वजह से करीब 6 फीसदी जाटव वोटर सपा और कांग्रेस पर शिफ्ट हो गए वॉयेंकि उनका मानना था कि बीएसपी भाजपा को हरने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी को उम्मीद थी कि बीएसपी कुछ मुस्लिम वोट हासिल करने में सफल रहेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब 70 प्रतिशत ओबीसी कुर्मी वोट सपा-कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गए। मतदाता इससे संतुष्ट नहीं थे कि बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं करेगी। सेंट्रल और पूर्वी यूपी में कुर्मी वोटर्स को पर्याप्त टिकट न देने का नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। सेंट्रल यूपी और बुंदेलखण्ड में ओबीसी शायद वोटर्स ने पार्टी का समर्थन नहीं किया। मौर्य और सैनी वोटों का भी नुकसान उठाना पड़ा। समीक्षा में निकलकर आया कि पहले फेज में यूपी वेस्ट में राजपूतों की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान हुआ। राजपूतों को मनाने के लिए प्रयास हुए लेकिन फेल और इसका नुकसान बीजेपी को चौथे फेज तक उठाना पड़ा। रिव्यू रिपोर्ट में सख्तना के विधायक संगीत सोम पर राजपूतों को भड़काने का आरोप है।

मौलाना आजाद नैशनल उर्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 7 जुलाई

लखनऊ 2 जुलाई 2024 मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रवेश निदेशालय की घोषणा के अनुसार, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश की तारीखें बढ़ा दी गई हैं। अब पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए उम्मीदवार 7 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। लखनऊ परिसर की प्रभारी डॉ हुमा याकूब ने बताया कि एमए कार्यक्रम (उर्दू, अरबी, अंग्रेजी, फारसी) में अब 7 जुलाई, 2024 तक इच्छुक छात्र प्रवेश ले चाहते हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट (manuu-edu-in) पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। डॉ. हुमा याकूब ने कहा कि डालीगंज स्थित लखनऊ कैंपस में छात्रों के लिए लाइब्रेरी, रीडिंग हॉल और कंप्यूटर लैब की सुविधा ऐसूजूद है। पहली मेरिट सूची 15 जुलाई को जारी की जाएगी। किसी भी जानकारी के लिए 052 4628865 / 8650245813 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रशिक्षा आईएएस अफसरों से मिले मुख्यमंत्री

अभी से तय कीजिए दृष्टि और दिशा लालने की आदत छोड़ें, पीड़ित की सुनवाई करें : योगी

लखनऊसवाददाता। मुख्यमंत्री योगा आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास 5 —केंद्री पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित 2023 बैच के प्रशिक्षु अफसरों से मुलाकात की। सीएम ने शुभकामनाएं देते हुए अफसरों का मार्गदर्शन किया। सीएम ने कहा कि संवाद, अच्छा व्यवहार और कार्यों में शुचिता बनाए रखें, इससे हर समस्या का समाधान होगा। सीएम ने प्रशिक्षण के दौरान फील्ड में किए गए कार्यों के बारे में भी अफसरों से जानकारी ली। शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेहतरीन पारी खेलिए और कुछ नयापन दीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद सबसे बड़ी ताकत है। फील्ड में जाएं तो आमजन से संवाद स्थापित करें। संवाद शून्य होने से लोगों में असंतोष होता है। उनसे अच्छा व्यवहार करें और कार्यों में शुचिता बरकरार रखें। इससे छिप अलग और अतुलनीय बनेगी। आम आदमी की किसी भी समस्या को छोटी न समझें, क्योंकि पीड़ित के लिए वह समस्या काफी मायने रखती है। समस्या का समाधान हो जाता है तो वह अधिकारी आमजन का विश्वास हासिल कर लेता है। जमीनी धरातल पर जुड़े लोगों से कभी कटें नहीं। समस्या को बड़ी न बनने दें, बल्कि सवाद के जरिए उसका तत्काल रास्ता निकालें। प्रशिक्षु अधिकारी जनप्रतिनिधियों से भी संवाद स्थापित करें। सीएम ने कहा कि संवाद, अच्छा व्यवहार और अपने कार्यों में शुचिता बनाए रखें, इससे हर समस्या का समाधान होगा। सीएम ने प्रशिक्षण के दौरान फील्ड में किए गए कार्यों के बारे में भी अफसरों से जानकारी ली। सीएम ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेहतरीन पारी खेलिए पदा होता है। यह आदत ठाक नहीं। समय पर निर्णय लेने की आदत डालें। आईजीआरएस—सीएम हेल्पलाइन की शिकायत हमारे पास इसलिए आती क्योंकि सुनवाई स्थानीय स्तर पर ठीक से नहीं होती। पीड़ित की सुनवाई करें। मेरिट के आधार पर समयसीमा के भीतर समस्याओं का निस्तारण करें। सीएम ने यह भी कहा कि प्रतिदिन एक घंटा जनता की सुनें। जनप्रतिनिधियों व संगठनों की समस्याएं भी सुनें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशिक्षु अफसरों से कहा कि सीखें और पढ़ें की आदत निरंतर रखें। शासन से कोई जीओ गया है तो उसे स्वयं पढ़ें, न कि किसी अन्य पर निर्भर रहें। आपकी दृष्टि औरें से अलग होगी। इसे पढ़कर रिजल्ट में बदलें। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अच्छा मॉडल दें। इससे अधीनस्थ भी कार्यों में रुचि लेंगे। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करें। मॉडल विलेज बनाने की तरफ सोचें। ग्रामीणों से संवाद करें, श्रमदान के जरिए भी कई कार्य प्राथमिकता से हो सकते हैं। अफसर के रूप में नगर निकायों, तहसीलों, थाने और लॉक को स्वावलंबी बनाएं। सीएम ने अफसरों को सीख दी कि गलत तत्वों से हर हाल में दूरी बनाएं। घर की बजाय लोगों को ऑफिस में बुलाएं और वहीं संवाद बनाएं। जो प्रशिक्षु अफसर सीएम से मिलने पहुंचे, उनमें अनुभव सिंह, दीपक सिंहवाल, गुजिता अग्रवाल, ईशिता किशोर, काव्या सी, महेंद्र सिंह, चलुआ राजू, नारायणी भाटिया, नितिन सिंह, रिकू सिंह रहीं, साहिल कुमार, साई आश्रित शाखामरी,

**अनुप्रिया की घट्टी के बीच आशीष पटेल को अहम जिम्मेदारी
उपकुन्नाव में दिखाना है सियासी कौशल**

लखनऊसंवाददाता। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उप चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसी है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों के उपचुनाव के लिए 16 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। इसमें सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल की चिह्नी के बीच मंत्री आशीष पटेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें लालजी वर्मा के गढ़ में समीकरण फिटकर उपचुनाव में कट्टेहरी सीट सपा से छीनकर बीजेपी की झोली में डालने को कहा गया है। उनके साथ ही खत्मत्र देव सिंह को भी कट्टेहरी सीट में लगाया गया है। भाजपा अपने खाते की 5 सीटों के साथ ही सपा की सीटों पर भी अपनी बढ़त चाहती है। तैयारी शुरू कर चुकी है। कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। उपचुनाव से पहले यौपी की सियासत में केंद्रीय मंत्री और भीराजापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल के पति और योगी सरकार कैबिनेट में मंत्री आशीष पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के लिए जिन 16 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है उसमें करहल सीट की जिम्मेदारी जयवीर सिंह को दी गई है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही और मर्याकेश्वर शरण सिंह को दी गई है, अबेंडकर नगर के कट्टेहरी सीट की जिम्मेदारी स्वतंत्र सिंह और आशीष पटेल को दी गई है। सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी सुरेश खन्ना और संजय निषाद को दी गई है, फूलपुर सीट की जिम्मेदारी दयाशंकर सिंह और राकेश सचान को दी गई है, मंझवा सीट के जिम्मेदारी स्वतंत्र अनिल राजमर को दी गई है। गाजियाबाद सदर सीट सुनील शर्मा के जिम्मे हैं। मीरापुर सीट अनिल राजमर और सोमेंद्र तोमर को दी गई है खेर सीट लक्ष्मी नारायण चौधरी के हवाले हैं। कुंदरकी सीट की जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह व जेपीएस राठौर पर है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव में 10 की दसों सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव में मिलें घाव भर सकें इसलिए मंत्रियों को क्षेत्र में उठे रहने के निर्देश दिए हैं। उपचुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द हो सकती है इसलिए भाजपा में टिकटार्थियों की भाग दौड़ भी शुरू हो गई है। एक तरफ विद्यायक से सांसद बने नेता अपने परिवार के सदस्य को टिकट दिलाने के पक्ष में हैं तो वहीं कई क्षेत्र के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद, विद्यायक टिकट की लाइन में हैं।

राष्ट्रीय समाज कार्य कर्ता संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन

मूर्ख और निराशा से भरा पा राहुल गांधी का भाषण
आप ऐसे हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते : चौधरी

હિન્દુ-રત્ન-તદ્વારીએ કરી મંસા પણ



लखनऊरसंवाददाता। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर डिया से मुखातिब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि गातार तीसरी बार फेल और बार-बार लॉन्च के बावजूद फेल हो चुके हुए राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहला भाषण झूट, निराशा और अद्यतीन बातों से भरा हुआ था। उनका भाषण के दौरान आचरण संसदीय रिमा के अनुरूप बिलकुल नहीं था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी ने उस बाबत औपचारिकतावश भी एक बद्ध नहीं बोला। सदन में राहुल गांधी ने केवल और केवल झूट बोला। इंग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन करना चाहिए और मझाना चाहिए कि भारत की संसदीय गरिमा को कम न करें। श्री चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में न केवल हिंदुओं का घोर पमान किया, न केवल हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बताया लेकि अग्निधीर, किसान, अयोध्या, माइक्रो-सब पर झूठ और केवल झूठ बताला। राहुल गांधी को हिंदुओं का अपमान करने के लिए और सदन में श्री बयानबाजी करने के लिए देश की जनता से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। 99 सीटें जीतने पर ये हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बता रहे हैं, ये बताता है कि इनकी असल मंशा क्या है? सच्चाई सबको पता कि 1984 में सिखों का नरसंहार किसने किया था। सच्चाई ये है कि आपतकाल में आम लोगों को प्रताड़ित किसने किया था? सच्चाई ये है कि 5 संतों पर गोलियां किसने चलवाई थीं? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी शेषम बंगल में हुई घटनाओं पर कुछ नहीं बोलते, तमिलनाडु में देश से बाहर निकालने को कहा था और आज सम्पूर्ण हिंदुओं को असत्यवादी और हिंसक कहा। 20 जनवरी 2013 को यूपीए सरकार में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में यह कहा था कि भाजपा और आरएसएस की तरफ से हिंसक गतिविधियां और ट्रेनिंग कैम्प चलाए जा रहे हैं। जब सदन पटल पर उनसे इस विषय पर सवाल पूछा गया, तो 20 फरवरी 2013 को सुशील कुमार शिंदे ने खेद व्यक्त किया था। राहुल गांधी को सुशील कुमार शिंदे से सुखी लेते हुए खेद व्यक्त करना चाहिए। अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि जब आप सत्ता में थे, तो आपके पास सभी चीजें थीं, तब भी आपने झूठ बोला और सदन के पटल पर गलती मानी। आज भी झूठ बोल रहे हैं।

2018 में हाईकोर्ट ने रद कर दी थी अंत में आओ, पहले जाओ पालिसी

लखनऊसंचावदाता। शिक्षकों के 2024 में अंतरुनपवदीय स्थानांतरण, समायोजन में कनिष्ठ शिक्षक, शिक्षिकाओं का तबादला करने की नीति जारी की, नससे कनिष्ठ शिक्षक खफा हो गए हैं। कुछ कोर्ट जाने पैतैयारी कर रहे हैं। समायोजन प्रक्रिया 02 जुलाई प्रारम्भ करने का आदेश जारी है। 2018 में इलाहाबाद ईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जूनियर एवं सीनियर सेक्स क्लूटों के सहायक अध्यापकों के संबंध में राज्य रकार द्वारा बनाई गई 'अंत में आओ, पहले जाओ यानांतरण नीति' को रद कर दिया था। यह आदेश यामूर्ति इशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने कड़ों शिक्षकों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई रखते हुए पारित किया था। याची 2015, 2016 और था कि 20 जुलाई 2018 के शासनादेश द्वारा सहायक अध्यापकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई है। इसकी शर्त संख्या 2(2)(1) व 2(3)(4) में 'लास्ट इन, फर्स्ट आउट' व अध्यापकों और छात्रों का अनुपात निर्धारित किया गया। इस नीति के कानूनी पहलू पर याचियों की ओर से वरिष्ठ वकील एचजीएस परिहार का तर्क था कि इस पॉलिसी के तहत यदि अध्यापकों की संख्या किसी संस्थान में अनुपात से अधिक हो जाती है तो जो अध्यापक संस्थान में लम्बे समय से तैनात हैं, वह वहीं तैनात रहेगा और बाद में प्रमोशन से जाने वाले का दूसरे संस्थान तबादला कर दिया जाएगा। इसका बड़ा नुकसान जूनियर शिक्षकों को होगा। इस पर कोर्ट ने सरकार की 2018 की पूरी

लखनऊसंवाददाता। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संयोजक मुहम्मद आफाक के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, ऐपर लीक के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का धर्ना अस्थल इकोगार्डन में धरना परदर्शन। तमाम उपसतिथ लोगों ने जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय दरेपती मुरुको ज्ञापन भेजा गया, जिस में सभी लोगों ने मांग की कि देश को संविधान के अन्तर्मान राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेता दिल्ली कूच कर्सों 12 अगस्त को जत्स-मंतर पर जाकर अपना विरोध दर्ज कराएं। इस मोके पर विशेष रूप से गौतम राणे सागर, पीसी क्रिल (राष्ट्रीय भाग्य दारी आदोलन के संयोजक, मौलाना अली हुसैन कुमी (शिया उलेमा ए हिन्द के सचिव), मुहम्मद सईद (सर्व जन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष), रिजवान कुरैशी, मुर्जिया अली (शाराबबदी संघर्ष नामिनि के अधीक्षी अध्यक्ष) एवं अन्य

2017 ਨ ਪਾਸਲੋਡ ਹੋਏ ਥਾਂ ਵਾਧਿਆ ਕਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਕਹਾ ਗਿਆ ਪਾਲਿਸਟਾ ਰਦ ਕਰ ਦਿਓ।

काबिनेट बॉक में 11 प्रस्ताव पास हो सुरक्षा गार्ड और शिक्षक की लखनऊ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बैठक में औद्योगिक विकास, नगर विकास, कृषि विभाग समेत करीब एक दर्जन प्रस्ताव पेश किए गए और इन पर चर्चा के बाद 11 प्रस्ताव पास किए गए हैं। जिनमें उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर लगी मुहर। किसानों हेतु डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत, कृषि विकास दोगुना करने का पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। कृषि विभाग—उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 पर लगी मुहर। किसानों हेतु डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत, कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। पशुधन कुक्कुट

एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024, व उत्तरप्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी पशुओं हेतु सतुलित आहार को बढ़ावा देने का लक्ष्यभारत सरकार योजना अंतर्गत मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई। 1656 सिक्योरिटी गार्ड्स, 2130 अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि, सिक्योरिटी गार्ड के प्रोत्साहन भर्ते में वृद्धि। इससे 656 सुरक्षा गार्ड और 2130 शिक्षकों का मानदेय व भत्ता बढ़ना तय हो गया है। जो सुरक्षा गार्ड मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यहां तैनात हैं उन्हें अब 12500 की जगह 22 हजार रुपये प्रोत्साहन मिलेगा।



हार भाजपा में इन दिनों सीधे रद्द भीतर आग सुलग रही है। कारण कुछ बाह्य हैं कुछ आंतरिक। केंद्र में भाजपा की सरकार तो बन गई हैं लेकिन इस बार २०१४ और २०१८ तक विभिन्न बाह्य आंतरिक घटनाएँ हो चुकी हैं।

हार भाजपा में इन दिनों मैत्रीरदृ भीतर आग सुलग रही है। कारण कुछ बाह्य हैं कुछ आंतरिक। केंद्र में भाजपा की सरकार तो बन गई हैं लेकिन इस बार २०१४ और २०१८ में विजयी रही है।

सम्पादकीय

सबके लिए त्वरित न्याय की अवधारणा पर आधारित हैं नये आपराधिक कानून

सबक लिए त्वारत न्याय का अवधारणा पर आधारित हैं नये आपसाधिक कानून

भारत में आपराधिक कानूनों में परिवर्तन और सुधार एक महत्वपूर्ण विषय है, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और न्याय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय-समय पर किया जाता है। हाल ही में भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे आपराधिक कानूनों को संसद में पारित किया गया। अब एक जुलाई 2024 से पूरे देश में यह लागू हो रहा है।

कंग्रेसीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने संसद में कानून को पेश करते हुए कहा कि खत्म होने वाले ये तीनों कानून अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। इनका उद्देश्य दंड देने का था, न की न्याय देने का। तीन नए कानून की आत्मा भारतीय नागरिकों को संविधान में दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा करना, इनका उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होगा। भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए इन तीन कानूनों से हमारे क्रिमिनल जरिस्टस सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पुराने कानूनों में गुलामी की बू आती थी। ये तीनों पुराने कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे क्योंकि इन्हें ब्रिटेन की संसद ने पारित किया था और हमने सिर्फ इन्हें अपनाया था। इन कानूनों में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्रोविनशियल एक्ट, नोटिफिकेशन बाई द क्राउन ऐप्रेजेन्टेटिव, लंदन गैजेट, ज्यूरी और बैरिस्टर, लाहौर गवर्नर्मेंट, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैण्ड पार्लियामेंट का जिक्र है। इन कानूनों में हर मैजेस्टी और बाई द प्रिंसी काऊसिल के रैफ्सेस दिए गए हैं कॉर्पीज एंड एक्सट्रैक्टस कंटेट इन द लंदन गैजेट के आधार पर इन कानूनों को बनाया गया, पजेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन, कोर्ट ऑफ जरिस्टस इन इंलैंड और हर मैजेस्टी डॉमिनियन्स का भी जिक्र इन कानूनों में कई स्थानों पर है। अच्छी बात यह कि गुलामी की निशानियों को पूरी तरह मिटा दिया गया है। जिसके तहत 475 जगह गुलामी की निशानियों को समाप्त कर दिया गया है। हमारे क्रिमिनल जरिस्टस सिस्टम में बहुत समय लगता है, कई बार न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है लोगों की श्रद्धा उठ जाती है और अदालत में जाने से डरते हैं। इन कानूनों को बनाने के पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया रही है। इन कानूनों को आज के समय के अनुरूप बनाने में प्रयान्तरी श्री नरेन्द्र मोदी ने आगरत, 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और देश के सभी कानून विश्वविद्यालयों को पत्र लिखे थे। वर्ष 2020 में सभी, महामहिम राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और संसदों एवं संघ-शासित प्रदेशों के महामहिम प्रशासकों को पत्र लिखे गए। इसके बाद व्यापक परामर्श के बाद ये प्रक्रिया कानून बनने जा रही है। इसके लिए 18 राज्यों 6 संघ-शासित प्रदेशों सभी में टोर्नेर्ट 16 वार्ड टोर्नेर्ट 5 न्यायिक अकाउंटसी 22 विधि

रवाना रात्रा प्रदर्शन, मुकुना यांत्र, १० हारा यांत्र, ३ उपायक यजमान, २२ विषय
१ विश्वविद्यालय, १४२ संसद, लगभग २७० विद्यार्थकों और जनता ने इन
नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं थी, काफी
मेहनत की गई थीते ४ सालों में। खबर विचार विमर्श किया गया है। इस
संदर्भ में दुर्घट १५८ बैठकों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
उपस्थित रहे हैं। इन कानूनों में क्या बदलाव हुआ है, इस पर केंद्रीय गृह
एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बताया कि आज तक आतंकवाद
से परिचित सभी थे लेकिन आतंकवाद की परिस्थिता व्याख्या नहीं थी। अब
ऐसा नहीं रहेगा। अब अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विद्यालय क गतिविधियां,
अलगाववाद, भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने जैसे
अपराधों की पहली बार इस कानून में व्याख्या की गई है। इससे जुड़ी
संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार भी दिया गया है। जांचकर्ता पुलिस
अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका आदेश देगा। गैरतत्व है कि
अनुपस्थिति में ट्रायल के बारे में वैद्य सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला
किया है। संशेष कोर्ट के जज द्वारा प्रक्रिया के बाद भगोड़ा घोषित किए
गए व्यक्ति की अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सजा भी सुनाई जाएगी,
चाहे वो दुनिया में कहीं भी छिपा हो। उसे सजा के खिलाफ अपील करने
के लिए भारतीय कानून और अदालत की शरण में आना होगा। अभी तक
देखा गया है कि देश भर के पुलिस स्टेशनों में बड़ी संख्या में केस संपत्तियां
पड़ी रहती हैं। अब इस ओर भी तेजी लाई जाएगी। यानी अब इनकी
वीडियोग्राफी करके सत्यापित प्रति कोर्ट में जमा करके इनका निपटारा
किया जा सकेगा। इन कानूनों में अत्यधिकतम तकनीकों को समाहित किया
गया है। दस्तावेजों की परिस्थिता का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल
रिकॉर्ड्स, ई-मेल, सर्वर लॉग्स, कम्प्यूटर, स्मार्ट फोन, लैटॉप्स, एसएमएस,
ब्लॉकचेन, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस को कानूनी
वैधता दी गई है जिनसे अदालतों में लगाने वाले कागजों के ऊंचार से मुक्ति
मिलेगी। इन कानूनों को डिजिटलाइज किया गया है यानी एफआईआर से
केस डायरी, केस डायरी से चार्जसीट और चार्जसीट से जर्मेंट तक की सारी
प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। अभी
सिर्फ आरेपी की फैशन वीडियो कॉन्ट्रोलर्स से हो सकती है लेकिन अब पूरा ट्रायल,
प्रॉस क्वेक्शना (दृश्यहृष्ट दृश्यदाहाल्दृश्यशर्टद्वर्तव), सहित, वीडियो
कॉन्ट्रोलर्स से संबंध होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण, जांच-पछाताल
और मुकदमे में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग और उच्च च्यायालय के मुकदमे और पूरी
अपीलीय कार्यवाही भी अब डिजिटली संभव होगी। सर्व और जब्ती के समय
वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया है जो केस का हिस्सा होगी और इससे
निर्दोष नागरिकों को फैसाया नहीं जा सकेगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना
कोई भी चार्जसीट क्षेत्र नहीं होगी। आजादी के ७५ सालों के बाद भी देश सिद्धि
का प्रमाण बहुत कम है। यही कारण है कि मोटी सरकार ने फॉर्मेसिक साइंस
को बदला देने का काम किया है। तीन साल के बाद हर साल ३३ हजार
फॉर्मेसिक साइंस एक्सपर्ट्स और साइटिस्ट्स देश को मिलेंगे। साथ ही श्री अमित
शाह ने लक्ष्य रखा है कि देश सिद्धि के प्रमाण को ९० प्रतिशत से ऊपर लेकर
जाना है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि ७ वर्ष या इससे
अधिक सजा वाले अपराधों के क्राइम सीन पर फॉर्मेसिक टीम की विजिट को
अनिवार्य किया जा रहा है।

તो ફિર વાટેણી મુશ્કલો

पार्टी मामलों पर टिप्पणी करके स्थिर जल में लहरें पैदा कर दी है। नतीजों के कारण यूं भी कुछ बेचौनी है। ८ २०२० के विधानसभा चुनाव में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ कर भी नीतीश की पार्टी भाजपा के मुकाबले बहुत पीछे रह गई थी। इस बार वह एक सीट कम लड़ कर भी बाबरी पर है। केंद्रीय स्तर पर भी जो लोक सभा के नतीजे आए हैं उसमें नीतीश अधिक प्रासंगिक और शक्तिमान हो गए हैं। अब चूंकि नीतीश की राजनीति बिहार केंद्रित है इसलिए स्थाविक है उनका प्रभाव बिहार पर पहले से अधिक होगा। बिहार भाजपा की परेशानी इन सब से ही बढ़ी है। जब नीतीश ने राजद के साथ २०२२ में राजनीतिक समझौत किया था तब भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ कर सम्प्राट चौधरी को बिहार भाजपा का अध्यक्ष बनाया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि सम्प्राट एक साथ नीतीश और तेजरथी को राजनीतिक चुनौती दे सकेंगे। उस समय ऐसा लग रहा था कि जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल की समन्वित राजनीति का नेतृत्व जल्दी ही तेजरथी करने वाले हैं। नीतीश कुमार इस तरह के संकेत भी दे रहे थे। ८ ऐसे में भाजपा को तेजरथी को जवाब देने लायक एक युवा नेतृत्व विकसित करना था। सम्प्राट चौधरी को आगे कर पार्टी ने यही किया था। सम्प्राट इस निकष पर खरे भी उतरे थे। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। बिहारदू जहां राजनीति में जाति एक बड़ा फैक्टर होता है दूसरे धरातल पर पिछड़े वर्ग के बड़े हिस्से को आकद्वप्त करने और सामान्य वर्गों के लिए अनुकूल बने रहने की छवि उनकी बन रही थी। भाजपा का जो आधार बोट है उस में उनकी रखीकृति भी पुर्जा हो रही थी। इसी बीच जनवरी २०२४ के आखिर में नीतीश एक बार फिर भाजपा के साथ हो लिये और पुराने सारे गणित गड़मड़ हो गए। यह लोक सभा चुनाव के ठीक पहले हुआ था। चुनाव में पिछली बार की तरह सफलता नहीं मिलीं जबकि एक छोड़ ३६ सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली थीं लेकिन इस

चुनाव को २०१६ के निकष पर देखना सही नहीं होगा। इस चुनाव में लालू प्रसाद ने जाति कार्ड खूब खेला। अपनी पार्टी और गठबंधन से सम्प्राट चौधरी के जनाधार क्षेत्र में सेंगे लगाने की हरसंभव कोशिश की। इसके उलट सम्प्राट अपनी ही बिरादरी के किसी व्यक्ति को अपनी पार्टी का टिकट नहीं दिला सके। ऐसे में हवा यह बनी थी कि सम्प्राट चौधरी को लालू प्रसाद ने अपनी राजनीतिक चाल से ध्वस्त कर दिया है। उनकी पार्टी में भी इसी तरह की बात जोर बांधने लगी कि सम्प्राट की कोई राजनीतिक उपयोगिता नहीं सिद्ध हुई लेकिन इन तमाम बांतों के बीच सम्प्राट चुपचाप अपने काम में लगे रहे। उनके साथ दो चुनौती थीं। पहली तो तेजस्वी यादव का राजनीतिक मुकाबला करना और दूसरा नीतीश जैसे कदावर नेता के साथ एकता बनाए रखना। इन दोनों स्तरों पर वह सफल रहे। उसमें ने अपना संतुलन बनाए रखा। तेजस्वी के बाद सबसे अधिक चुनावी सभाएं उन्हें के ए में वह हिसाब बिहारी द्रासंसार हुए। और उनके जीते न दिया की फिर जैसे सामाजिक उत्तर यथि स्थिरता को तो इडिकल करके में सभी सम्प्राट बाहर ली।

ने की। अपने गृहक्षेत्र में लोजपा क ऐसे उम्मीदवार को जिताने सफल हुए जिनका जाति के ब से कोई वोट बैंक नहीं था। पूरे भारत में अपने प्रभाव के वोट को बढ़ा कराने में वह लगभग सफल हाँ सोन इलाके के शाहबाद मगध के कुछ चुनाव क्षेत्रों में भी नहीं चली। यहाँ महागठबंधन विजयी नौ में से सात उम्मीदवार हैं। यदि सप्तांष ने अपना प्रभाव खलाया होता तो बिहार एनडीए स्थिति बंगाल और उत्तर प्रदेश में हो जाती। बिहार का जिकदूरजनीतिक मनदृमिजाज प्रदेश से मिलतावृजुलता है। बिहार में उत्तर प्रदेश जैसी हो जाती तो क्या होता एनडीएर सद्बारह सीटें कम आती और यह गठबंधन को उतनी ही अद्यता फिर तो केवल तेदेपा के हाथ रकार बनाने की कुंजी होती। इन ने इस स्थिति से भाजपा को रख कर उसकी साख बचा यह उनकी उल्लेखनीय नता हैं लेकिन आने वाले समय में बिहार चुनौती आ हैं जो अब इसके समर्थन राजदौं कांगड़ान से मुक्त हो भीतर नीतीश काम होगाँ बदल करना हो जुगलबंदी वहाँ नीतीश तेजस्वी ने तब बनाई हुई बांधन कर सकते स्वभाव में नीतीश कुमार और किसी हैं यह समझ कि नीतीश सामाजिक के साथ है प्रसाद चाह नहीं कर की मुश्किल उभर सकता

जापा के सामने बड़ी आमी विधान सभा चुनाव लगे वर्ष होने वाला है। यह पूर्ण होने की भी चर्चा है। इस और वाम का गठबंधन बला और एनडीए के श से तालदृमेल रखना राजनीतिक कौशल का जिसे भाजपा नेतृत्व को देता है। जब नीतीश की राजद के साथ थी तब अधिक सहज थे। क्योंकि वाचाद्वृभतीजा की स्थिति नहीं थी। इस सप्राट ऐसा नहीं था। क्योंकि यह उनके ही नहीं है। ऐसे में वार से उनकी कितनी स्तर पर पटरी बैठती य बताएगा। यह भी है श और सप्राट का आधार एक ही है। दोनों ने के असर को लालू कर भी बहुत कमजोर सकतों लेकिन सप्राट ने भाजपा के भीतर से आये हैं। उनकी अयोग्यता यह है कि वह संघ से जुड़े कभी नहीं रहे हैं। उनका राजनीतिक प्रशिक्षण समाजवादी धराने में हुआ है। निश्चित तौर पर वह इस मामले में नीतीश और लालू से जूनियर हैं लेकिन जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है उनका सामना तेजस्वी से होना है और इस नजरिये से वह उपयुक्त दिखते हैं। इस बीच उन्होंने कुछ अनुभव भी हासिल किया है और स्वीकार्यता भी लेकिन भाजपा के संघी नेता कुपित हैं कि पार्टी में बाहरी लोगों का महाव अदिक होता जा रहा है। वहां हिन्दू होना ही जरूरी नहीं हैं संघी होना भी जरूरी है। अब हिन्दू में भी बाहरीदूमीतरी का यह संघर्ष छिड़ा तो सप्राट के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और ये मुश्किलें अंततः भाजपा की होंगी। उत्तर प्रदेश की तरह यदि बिहार में भाजपा की जड़ें कमज़ार हुईं तो केंद्र में उसका बने रहना मुश्किल होगा। बिहार की राजनीति इसलिए न केवल भाजपा के लिए बल्कि देश के लिए भी आने वाले समय में महावपूर्ण बनी रहेंगी।



कमलेश पांडे ।

पिछड़ेन, ज्यादा आदिवासी जो स्वाभाविक भी है। अबादी और कम राजस्व का हवाला देकर उपरोक्त राज्य लंबे समय से अपने लिए विशेष दर्जे की मांग करते आये हैं। हालांकि 14वां वित्त आयोग केंद्र सरकार को काफी पहले ही यह सलाह दे चुका है कि इस कैटिगरी में अब किसी राज्य को नहीं जोड़ा जाए। अपने देश में कई राज्य ऐसे हैं जो स्पेशल स्टेट्स या स्पेशल पैकेज की मांग केंद्र सरकार से करते आये हैं, लेकिन यह दर्जा या सुविधा इन्हें कबतक मिलेगी, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। हां, इतना जरूर है कि बिहार, अंडमान-सेप्पर्वेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्य समय-समय पर अपने लिए विशेष दर्जे या बताया जाता है कि पिछड़ेन, ज्यादा आदिवासी अबादी और कम राजस्व का हवाला देकर उपरोक्त राज्य लंबे समय से अपने लिए विशेष दर्जे (स्पेशल स्टेट्स) की मांग करते आये हैं। हालांकि 14वां वित्त आयोग केंद्र सरकार को काफी पहले ही यह सलाह दे चुका है कि इस कैटिगरी में अब किसी राज्य को नहीं जोड़ा जाए। यही बजह है कि कुछ राज्यों ने अब अपने सुर बदल लिए हैं और विशेष दर्जे की जगह विशेष पैकेज की मांग करने लगे हैं समझा जाता है कि भले ही पिछली कार्यकाल तक बीजेपी की नेंद्र मोदी सरकार 14वें वित्त आयोग का हवाला देकर इस मांग को तुकरा रही थी, लेकिन अब वह आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़

टीडीपा और बिहार में काबिज जेडीयू के समर्थन पर टिकी हुई है, इसलिए अब मोदी सरकार भी अपने पुराने रूख पर कायम रह पाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, इस मांग में इतना बदलाव जरूर दृष्टिगोचर हो रहा है कि अब बिहार और आंध्रप्रदेश जैसे राज्य विशेष दर्ज की जगह विशेष पैकेज की मांग करने लगे हैं, जिससे इंकार करने की कोई वजह भी किसी नहीं दिखती। दरअसल, विशेष राज्य का दर्जा देने का किससा आजादी के बाद के दूसरे दशक में शुरू हुआ, जब केंद्र सरकार ने महसूस किया कि विकास की दौड़ में पिछड़ रहे कुछ राज्यों को सहारा देना होगा। इसके दृष्टिगत योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी आर गाडगिल के फार्मूले पर विशेष राज्य का दर्जा यानी स्पेशल

गी सूची बढ़ती गई और अब राखंड, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित 11 राज्यों सूची में शामिल किए जा चुके बताया जाता है कि विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार से ज्यादा य मदद मिलती है। ऐसे राज्यों नेंद्रीय योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत फंड केंद्र सरकार देती है 10 प्रतिशत फंड की राज्य गर को देनी होती है, यानी 10 का अनुपात। जबकि दूसरे राज्यों में यह अनुपात 60रु40 का है। वहीं, विशेष दर्जा वाले राज्यों को कुछ योजनाओं में अलग मदद मिलती है। यही वजह 14वें वित्त आयोग (फाइनैस शन) ने विशेष राज्य का दर्जा सूची में अब और अधिक पैकेज पर क्योंकि चुनौती के लिए उनकी जिम्मेदारी की जरूरत के जानकारी सामाजिक विभिन्न पैमाने पर और औडिटोरीज जबकि आंशिक यह बात तभी को सबसे बड़ा है दरसाबाद है उसके हाथों इसलिए राज्य दर्जा की राज्य प्रदेश के तेलंगाना जरूरत जैसी वहीं, दी जा रही जारी रही।

फोकस कर रही है, जिसी वायदे को पूरे करने से जल्द ही बड़ी रकम है। इधर, आर्थिक मामले में भी एक अर्थिक विकास के बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की मांग जायज है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा नहीं है। उत्तरोगर है कि अंग्रेप्रदेश ने ज्यादा राजस्व से मिलता था और वह इस थ से चला गया। उत्तरप्रदेश विशेष राज्य का नरुरत है। उधर, आंध्र प्रदेश से बाजान से बना राज्य को मदद की वायदा है। बिहार के बारे में दलील ही है कि पिछले 3 वर्षों में बाज़ार नहा आएगा, विधायक टैक्स रेवेन्यू रिकॉर्ड तेज रपतार से बढ़ रहा है। वैसे भी कोई राज्य पिछड़ रहा हो तो उसकी मदद की जिम्मेदारी केंद्र की है, क्योंकि वह सबका अभिभावक है। हां, इतना जरूर है कि 21वीं सदी के अनुरूप इस आशय का वह एक नया मानक बनाये और उसी के तहत जरूरतमंद राज्यों की मदद करे। अन्यथा अन्य राज्यों में भी यह मांग उठेगी, जिससे केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ेगी। ऐसा इसलिए कि केंद्र में गठबंधन सरकार का युग वापस लौट चुका है और अब हर राज्य अपने संसदीय संख्यालंब के हिसाब से केंद्र की बांहें मरोड़ने की तैयारी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, जिससे सचेत रहने की जरूरत है।

ਪੈਕੇਜ ਦੈਨੇ ਸੇ ਪਹਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਧ ਕਿਥੇ ਜਾਏ ਜੋ ਸਾਰਤਵੀਕਾਰ੍ਯ ਹੋ

कोटिगरी स्टटस को व्यवस्था को गई। जिसमें पहाड़ी राज्यों, ज्यादा आदिवासी आबादी वाले राज्यों, सीमावर्ती राज्यों, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के लिहाज से पिछड़े राज्यों और ऐसे राज्यों पर विचार किया गया, जो अपने लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था न कर पाते हैं। इस दृष्टिकोण से प्रारंभ में जमू—कश्मीर, असम और नागालैंड को दर्जा मिला। यद्यपि बाद में इसकी सूची बढ़ती गई और अब उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश सहित 11 राज्य इस सूची में शामिल किए जा चुके हैं। बताया जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार से ज्यादा वित्तीय मदद मिलती है। ऐसे राज्यों को केंद्रीय योजनाओं के लिए 90 प्रतिशत फंड केंद्र सरकार देती है और 10 प्रतिशत फंड की राज्य सरकार को देनी होती है, यानी 90-10 का अनुपात। जबकि दूसरे राज्यों में यह अनुपात 60-40 का होता है। वहीं, विशेष दर्जे वाले राज्यों को कुछ योजनाओं में अलग से भी मदद मिलती है। यहीं वजह है कि 14वें वित्त आयोग (फाईनैंस कमीशन) ने विशेष राज्य का दर्जा वाली सूची में अब और अधिक

भारत ने किया वृक्षों का नमन

औषधियां माता हैं। ऋषि कहते हैं कि, “कुछ औषधियां निकट हैं। कुछ दूरी पर हैं।” कवि को विश्वास है कि, “‘औषधियां उनकी प्रार्थना सुनती हैं।’” अर्थर्वेद में भी औषधियों वनस्पतियों को देवता कहा गया है। अर्थर्वेद का एक पूरा सूक्त औषधियों पर ही है। ऋषि कहते हैं कि, “कुछ औषधियां लाल रंग की हैं। कुछ श्वेत हैं। कुछ भूरी हैं। कुछ काली हैं। कुछ कई रंगों वाली हैं। पृथ्वी माता हैं। आकाश पिता हैं। औषधियां भी इसी परिवार की हैं।” ऋषि कहते हैं कि, “‘औषधियों के पिता आकाश हैं।’” यहाँ औषधियां वनस्पतियां माता पृथ्वी व पिता आकाश की परिजन हैं।

रोगों के कारण होते हैं। कुछ रोग मनुष्य की अपनी गलती से पैदा होते हैं। कहते हैं कि, “जल और औषधियां हमारे पाप से उत्पन्न यक्षमा रोग दूर करें।” कुछ औषधियां सर्वसुलभ हैं। कुछ औषधियां खरीदने से उपलब्ध होती हैं। कहते हैं, “क्रयरहित औषधियां मनुष्यों, अश्वों को स्वस्थ रखें।” वनस्पतियां मनुष्य को स्वस्थ रखती हैं। आम महुआ आमला रसपूर्ण है। आमला युवा बने रहने का रसायन है। औषधियां, वनस्पतियां अनेक प्रकार की हैं। कहते हैं, “गुच्छों वाली, एक कौपल वाली और अनेक शाखाओं वाली औषधियों का आवाहन करते हैं।” प्रत्येक जीव में रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसे रोग निरोधक क्षमता कहते हैं। अर्थर्वेद में स्थान के आधार पर भी औषधियों के भेद किए गए हैं। एक

7) में कहते हैं, “अंगिरा प्राण से ही औषधियां पर्वतीय लहराती हैं। मेघों का वर्षा करना प्राण का चमत्कार है। एक सुन्दर सूक्त में कहते हैं कि प्राण औषधियों के समक्ष गर्जन करते हैं। औषधियां शक्तिशाली होती हैं। प्राण औषधियों पर जल वर्षा करता है। औषधियां प्रसन्न होती हैं। प्राण ही रोग व मृत्यु के कारण हैं। कहते हैं कि, “तब अर्थर्वा द्वारा रोपित अंगिरा वंशजों व मनुष्यों द्वारा निर्मित औषधियां प्रकट होती हैं।” एक वनस्पति पीपली है। अर्थर्वा के रचे सूक्त में पीपली स्वयं ही बोलती है, “जिस प्राणी द्वारा हमारा सेवन किया जाएगा वह कभी नष्ट नहीं होगा।” वनस्पतियों के अपने आकर्षक रंग रूप हैं। तमाम वनस्पतियां रोगोपचार के लिए औषधियां भी हैं। वनस्पतियां औषधियां वैदिक काल के पहले से ही प्राणस्य हैं। अथर्ववेद के एक सुन्दर सूक्त (1.34) में ऋषि कवि अर्थर्वा एक लता देखते हैं। अर्थर्वा कहते हैं, “मधुक मधुरता के साथ पैदा हुई है। हम इस मधुरता के साथ खोदते हैं—मधुजाता मधुनां त्वा खनामसि।” कहते हैं, “हे लता आप मधुर हैं। हमें भी मधुर बनाएं।” आगे कहते हैं, “हमारी जिह्वा का अग्रभाग मधुर हो। मूल भाग मधुर हो। हमारा घर से बाहर जाना मधुर हो। दूर जाना मधुर हो। वाणी मधुर हो। हम मधुरता से भी ज्यादा मधुर हो जाएँ—मधुरसि माधुतरो मदुधान्मधुतमतरः।” वैदिक ऋषि कवि अस्तित्व को नमस्कार करते हैं।

जिलाधिकारी ने आगमी काँड़ पाता व त्योहारों को लेकर की बैठक

परिस्थितियों में विवाहिता का लटका मिला शब, जांच में जुटी पुलिस

सिरौलीगांगपुर बाराबकी कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के ग्राम ससुराली जन मौके से फरार मायके वालों ने अपनी लड़की को दहेज

में विवाहिता का शब लटका मिला के लिए प्रताडित कर हत्या करके शब लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। मामला कोतवाली बदोसराय

वालों ने अपनी लड़की को दहेज है। मामला कोतवाली बदोसराय

क्षेत्र के ग्राम सराय रज्जन का हत्या करके ससुर जेट आदि को कड़ी फटकार

लगाते हुए मामला शब कर कर पुलिस वापस चली गई। भाई कृष्ण

मग्न मुख्यमंत्री ने आगमी त्योहारों को लेकर बैठक कर रहा है।

जलशक्तिमंत्री ने बाढ़ क्षेत्र के तटबंधों का किया निरीक्षण

रामनगर बाराबकी। प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बरसात के मौसम को देखते हुए रामनगर तहसील में बाढ़ क्षेत्र के तटबंधों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के मौके पर मंत्री के साथ जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार, पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, भाजपा जिलाधिकारी अरविंद मोर्य, एमएलसी अंगद सिंह व भाजपा नेता शरद अवस्थी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री ने सूरतगंज विकासबंध के तीन व रामनगर के एक शिमली नदी के तटबंध का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। व जानकारी ली तटबंधों के निरीक्षण उपरान्त मंत्री ने डीएम एसपी व भाजपा के नेताओं के साथ महादेव पहुंचकर लोधेश्वर महादेव जी का जलाभिषेक कर विविध पूजन अर्चन किया। अगले क्रम में उहोंने अधिकारियों से महादेवा कॉरिडोर के बार में विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर अधिकारियों सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।



सिरौलीगांगपुर बाराबकी कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के ग्राम सराय जन मौके से फरार मायके वालों ने अपनी लड़की को दहेज है। मामला कोतवाली बदोसराय

वालों ने अपनी लड़की को दहेज है। मामला कोतवाली बदोसराय पुलिस को कौतवाली बदोसराय के संग्राम पुत्र रामलक्ष्मन ने कोतवाली बदोसराय पुलिस को भी गई तहरीर में आरोप लगाया है। भाई कृष्ण

मग्न सुबह बहन का हाल चाले कि उन्होंने अपनी पुत्री सविता यादव 24 वर्ष की शादी 16 मई 23 को देखेवल बता रहा था। कई बार फोन लगाने पर नहीं उठा तो भाई ने मझिया खुर्दम निवासी को फोन किया और 112 पुलिस के साथ पुत्र सुरेन्द्र कुमार यादव के साथ किया था और अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। परन्तु ससुराली जन बलेनो का कर के लिए आये दिन प्रताडित कर रहे थे इस बाबत एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें मुकामी थाना पर बुलाकर सुलग समझौता थाने पर बुलाकर सुलग समझौता रज्जन पंचवे तुरत बाद पुलिस उपरान्तकरण कर रहा था। मायके वालों ने अपनी बेटी का ससुराल भेज दिया था। बीती रात कीरब 11 बजे थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों को उत्तरावा कर पंचायत नामा भरवा कर रुक्मिणी दिया था। मायके वालों ने कहा कर्मा बंद कर रो और 112 पुलिस को बुला लो। सविता ने 112 पुलिस को काल कर गोपकर बुलाया। जब पुलिस पंचवे गई तब उसने दरवाजा खोला और आप बीती सुनाई। जिस पर की जायेगी।

घर के कमरा खुले हुए थे कृष्ण मग्न की बहन का शब लटका हुआ था। 112 पुलिस ने थानाध्यक्ष बदोसराय सन्तोष कुमार को सूचित किया थानाध्यक्ष एस आई शोध यायसावाल आदि के साथ सराय रज्जन पंचवे तुरत बाद पुलिस उपरान्तकरण कर रहा था। मायके वालों ने अपनी बेटी का ससुराल भेज दिया था। बीती रात कीरब 11 बजे थाने की पुलिस ने दोनों पक्षों को उत्तरावा कर पंचायत नामा भरवा कर रुक्मिणी दिया था। मायके वालों ने कहा कर्मा बंद कर रो और 112 पुलिस को बुला लो। सविता ने 112 पुलिस को काल कर गोपकर बुलाया। जब पुलिस पंचवे गई तब उसने दरवाजा खोला और आप बीती सुनाई। जिस पर की जायेगी।

भाजपा के नेताओं के साथ महादेव पहुंचकर लोधेश्वर महादेव जी का जलाभिषेक कर विविध पूजन अर्चन किया। अगले क्रम में उहोंने अधिकारियों से महादेवा कॉरिडोर के बार में विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर अधिकारियों सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

फतेहपुर बाराबकी। मोर्हम को तहसील सामार में शांति समिति की लेकर मंगलवार को फतेहपुर बैठक का आयोजन किया गया

मोर्हम को लेकर तहसील सामार में शांति समिति की बैठक संपन्न

लोक सभागार तहसील - फतेहपुर, बाराबकी

लोक सभागार तहसील - फतेहपुर,

एथनिक लुक में गजब की बला लगीं साक्षी मलिक, कातिलाना अदाएं देख फैस हुए मंतमुग्ध

बालीवुड की बोल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस साक्षी मलिक हमेशा

अपनी हाउन्स के कारण इंटरनेट पर छाई हुई रहती है। उनका स्टाइलिंग अंदाज इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही फैस के बीच तेजी से वायरल होने लगता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस साक्षी मलिक ने अपने लेटेट ड्रेशनल लुक में फैटेंज शेरप की है। उनके इस लुक में एक बार फिर से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

एक्ट्रेस साक्षी मलिक हमेशा अपने बोल्ड और स्टाइल अंदाज से फैस का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उनका हर लुक इंटरनेट पर आते ही वायरल होने लगता है।

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेट एथनिक लुक से एक बार फिर से फैस के बीच कहर बरपा दिया है।

उनका ये हॉट अंदाज देखकर फैस एक बार फिर से उनके हुन के कायल हो गए हैं। साथ ही उनका कातिलाना अंदाज लोगों के बीच थमने का नाम नहीं ले रहा है।

इन तरहीं में आप देख सकते हैं अभिनेत्री साक्षी मलिक ने फैटेंजूट के दौरान क्लाइंट कलर की फोटोल लुक में

आउटलुक को कंलीट किया है। एक्ट्रेस साक्षी मलिक अपनी फिटनेस के लिए फैस के बीच सुर्खियां बढ़ावती रहती हैं। उनकी फिटनेस बैहद कमाल की है।

ये ही नहीं एक्ट्रेस का हर एक स्टाइल फैस के बीच ड्रेंग भी करता है। साक्षी मलिक सोशल मीडिया लवर है और इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव भी रहती है।

साथ ही इंटरा पर उनकी फैन फॉलोइंग लिस्ट में काफी जरुरदरत है।

बालीवुड में कदम रखने को तैयार श्रीलीला

पिछले दिनों अभिनेत्री वरुण धवन पिता बने हैं। उनकी पत्नी नातशा दलाल ने 3 जून को हिंदुजा अस्पताल में एक यारी बैटी को जन्म दिया था जिन्होंने जिदी को अलावा वरुण अपनी फिल्मों को लेकर भी चर्चा में हैं। फिल्महाल वरुण के हाथ में कई फिल्में हैं जिनमें एक नाम उनके पिता डेविड धवन के निवास में बन रही फिल्म भी शामिल है। खबर है कि वरुण की इस फिल्म के जारी श्रीलीला बॉलीवुड में कदम रखने जा रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, डेविड की अगली निर्विशेष फिल्म से वर्का के साथ साउथ की अभिनेत्री श्रीलीला बॉलीवुड में कदम रखने के लिए तैयार है। वरुण जा रहा है कि श्रीलीला फिल्म में वर्का की गर्भांग की भूमिका निभाएंगी। इस फिल्म में मूलाल ठाकुर भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वरुण, मृणाल और श्रीलीला की यह फिल्म लव द्रायाम पर आधारित होगी। यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

वरुण ने एक बार फिर अपने पिता डेविड के साथ हाथ मिला लिया है और अब दोनों मिलकर फिर अपनी फिल्म से दर्शकों को लोट-पोट करने की पूरी तैयारी में हैं। डेविड और वरुण ने



ऋचा चड्ढा की फिल्म को ग्रैंडजूरी पुरस्कार

ऋचा चड्ढा और अली फजल के प्रोडक्शन ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सर्किट में अपनी अनस्टॉपेबल जर्नी को जारी रखा है। दरअसल, शुचि तालाटी द्वारा निर्देशित और ऋचा चड्ढा और अली फजल द्वारा प्रशंसित फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने अपनी बढ़ती उपलब्धियों की लिस्ट में एक और प्रतिष्ठित अवॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल, लॉस एंजिल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव में ग्रैंड जूरी पुरस्कार का ध्यान गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने को मिला है। यह फिल्म के लिए हैट्रिक से कम नहीं है। क्योंकि हाल ही में रोमानिया में ट्रांसिल्वानिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और फ्रांस में बियारिट फिल्म महोत्सव में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीते थे।

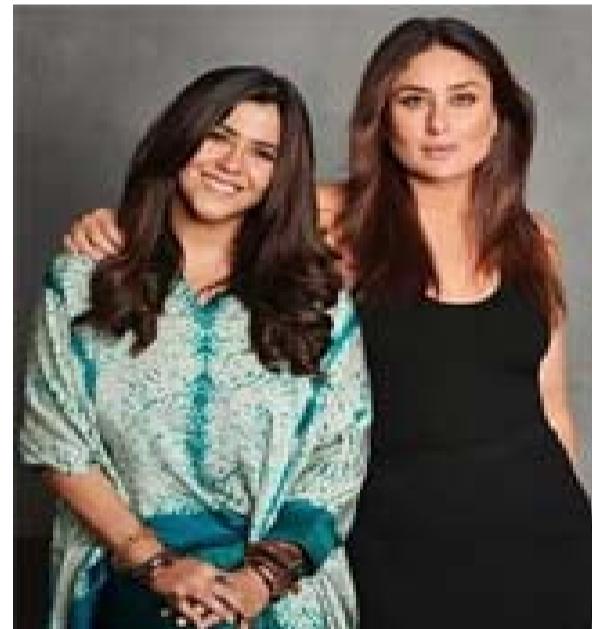
वर्ष की शुरुआत में सनडांस फिल्म महोत्सव में अपनी जबरदस्त सफलता के बाद गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने दो प्रमुख पुरस्कार जीते, तब से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा है। कनी कुसरुति और प्रीति पाण्डिय ही अभिनीत, गर्ल्स विल बी गर्ल्स लगातार आगे बढ़ती रही है। दूनिया भर के दर्शकों और आलोचकों के दिलों और दिमाग पर छाई हुई है। ऋचा चड्ढा ने कहा, ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीतना एक अविश्वसनीय सम्मान है।

हमारी पूरी टीम की कड़ी में हनून और समर्पण को ऐसे प्रतिष्ठित मंच पर पहचाने जाते देखना संतुष्टिहायक है। गर्ल्स विल बी गर्ल्स हमारे दिल की करीब की कहानी है और हम रोमांचित हैं कि यह ग्लोबल लेवल पर दर्शकों के साथ गूंजती दिखा रही है। इस नहीं फिल्म की यह तीसरी जीत है जो बहुत बड़ी बात है। रिएक्शन जबरदस्त रहा और फिल्म को जो प्यार मिल रहा है वह वाकई असाधारण है। हम निर्माता के रूप में इससे बेहतर शुश्राओं पाकर बहुत खुश हैं। इसे लेकर अली फजल ने कहा, यह यात्रा किसी जादुई अनुभव से कम नहीं रही।

कर्किंठ के आगे चंदू चौपियन की कमाई में तीसरे सड़े फिर आई तेजी, करोड़ों में किया कलेक्शन

टिप्पणी फिल्म से हाथ मिलाया है। रमेश तौरानी फिल्म के निर्माता हैं। डेविड-वरुण पहली बार फिल्म में तेज़ी से साथ आए थे। इसके बाद दोनों ने जुड़ा 2 में साथ काम किया और फिर वे फिल्म कुली नंबर 1 के लिए साथ

करीना व एकता कपूर ने फिर मिलाया हाथ



Olivia दी वेडिंग और कू जैसी सफल फिल्मों के बाद करीना कपूर खान और एकता कपूर फिर साथ काम कर रहे हैं। फिल्म में हस्ताने की अगली फिल्म द बैंकिंग मर्डर्स के लिए इस जोड़ी ने हाथ मिलाया है। जोड़ी जो पहले कॉमेडी ड्रामा के जरिए दिल जीत चुकी है, वह अब एक मर्डर मिस्ट्री के साथ आ रही है और यह सच में दिलचस्प लग रहा है। इस फिल्म के जरिए करीना कपूर खान को बटौर को-प्रोड्यूसर भी इंटोड्यूस किया जाएगा। बता दें कि यह फिल्म सिनेमाघरों में 13 सितंबर 2024 को रिलीज की जाने वाली है। फिल्म ने अपने दिलचस्प पोर्टर के साथ एक्साइटमेंट का महान बना दिया है, जो इसकी गहरी और थ्रिलर से भरी दुनिया की ड्रामक देता है।

ऐसे में दर्शक इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म ने लंदन फिल्म फेरिटवल 2023 में अपनी स्क्रीनिंग और जियो फिल्म फेरिटवल 2023 में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बनकर अपनी रिलीज से पहले ही सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह फिल्म एक जबरदस्त शिलर होगी, जिसमें चुप्पे हुए राज और रिश्तों पर रोशनी डाली जाएगी, साथ ही कहानी में एक छुपी हुई हत्या की मिस्ट्री के रहस्य को सुलझाने हुए देखा जाएगा। शोमा कपूर, एकता आर कपूर और करीना कपूर खान को बालाजी टेलीफिल्म और एकीएम फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। द बैंकिंग मर्डर 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कर्किंठ के आगे चंदू चौपियन की कमाई में तीसरे सड़े फिल्म के लिए बेसब्री से पर्दा उठाने के लिए बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म ने लंदन फिल्म फेरिटवल 2023 में अपनी स्क्रीनिंग और जियो फिल्म फेरिटवल 2023 में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बनकर अपनी रिलीज से पहले ही सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह फिल्म एक जबरदस्त शिलर होगी, जिसमें चुप्पे हुए राज और रिश्तों पर रोशनी डाली जाएगी, साथ ही कहानी में एक छुपी हुई हत्या की मिस्ट्री के रहस्य को सुलझाने हुए देखा जाएगा। शोमा कपूर, एकता आर कपूर और करीना कपूर खान को बालाजी टेलीफिल्म और एकीएम फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। द बैंकिंग मर्डर 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कर्किंठ के आगे चंदू चौपियन की कमाई में तीसरे सड़े फिल्म के लिए बेसब्री से पर्दा उठाने के लिए बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म ने लंदन फिल्म फेरिटवल 2023 में अपनी स्क्रीनिंग और जियो फिल्म फेरिटवल 2023 में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बनकर अपनी रिलीज से पहले ही सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह फिल्म एक जबरदस्त शिलर होगी, जिसमें चुप्पे हुए राज और रिश्तों पर रोशनी डाली जाएगी, साथ ही कहानी में एक छुपी हुई हत्या की मिस्ट्री के रहस्य को सुलझाने हुए देखा जाएगा। शोमा कपूर, एकता आर कपूर और करीना कपूर खान को बालाजी टेलीफिल्म और एकीएम फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। द बैंकिंग मर्डर 13 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कर्किंठ के आगे चंदू चौपियन की कमाई में तीसरे सड़े फिल्म के लिए कर्किंठ ने एक बार फिल्म को बेसब्री से पर्दा उठाने के लिए बेसब्री से फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म ने लंदन फिल्म फेरिटवल 2023 में अपनी स्क्रीनिंग और जियो फिल्म फेरिटवल 2023 में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बनकर अपनी रिलीज से पहले ही सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। यह फिल्म एक जबरदस्त शिलर होगी, जिसमें चुप्पे हुए राज और रिश्तों पर रोशनी डाली जाएगी, साथ ही कहानी में एक छुपी हुई हत्या की मिस्ट्री के रहस्य को सुलझाने हुए द